VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 1130489

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Maitreya Kumar Shukla

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English

HINDI.

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)
GENERAL STUDIES (Paper III)

तारीख
Date

28/08/2022

केंद्र
Centre ANAND VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL BHOPAL

Maltee

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनानें के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

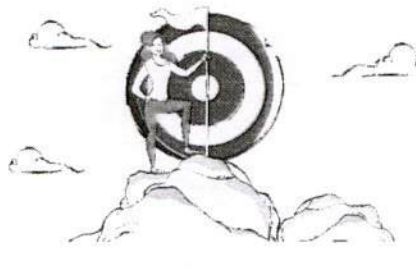

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे
Time Allowed: **Three** Hours

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ-साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Fiscal policy can be a key tool to reduce income inequality as well as make the poorest and the downtrodden a part of the country's growth story. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

राजकोषीय नीति से तात्पर्य केंद्र की सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से बनायी गयी एक व्यापक समष्टि अर्थशास्त्रीय नीति से है जिसमें महंगाई, रोजगार, आयात-निर्यात, कर आदि सभी मुद्दे शामिल होते हैं।

राजकोषीय नीति के लाभ ->

1) देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कर, स्कालरशिप, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर सकती है। जैसे- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।

2) यह वित्तीय समावेशन सुनिश्चित

करने के लिए विभिन्न पहलें कर सकती है। जैसे- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, अटल पेंशन योजना आदि।

3) वित्तीय रूप से सशक्त होकर ही समाज के वंचित वर्ग मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे तथा समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

4) इसके अलावा इसके अंतर्गत महंगाई कम करने, राजस्व बढ़ाने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने तथा आधारभूत संरचना निर्माण जैसे कदम उठाए जाते हैं, जो अंततः देश के हर वर्ग का ही विकास सुनिश्चित करती है। जैसे- भारतमाला परियोजना

राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन में व्याप्त प्रशासनिक खामियों को दूर किए जाने की जरूरत है ताकि डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में यह अपनी भूमिका निभा सके।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी काफी सहायक होगा। विस्तारपूर्वक समझाइए। साथ ही, इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Digitizing land records will go a long way in ensuring land reforms as well as lessening the burden on the Indian Judiciary. Elaborate. Also, state the measures taken in this context. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भारत द्वारा अपनाए गए व्यापक भूमि सुधारों का ही हिस्सा है जिसके अंतर्गत भूमि के मालिकाना हक, हस्तांतरण, उपयोग संबंधी सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यमों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है।

डिजिटलीकरण के लाभ =>

1) भूमि सुधार =>
- भूमि की विशेषताओं के अनुरूप लक्षित नीति निर्माण
- विवाद संबंधी मामलों में पारदर्शी कार्यवाही
- हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान होगी।

2) न्यायिक लाभ ⇒ न्यायपालिका की दस्तावेजों तक तेज उपलब्धता सुनिश्चित।
→ बिना किसी छेड़छाड़ के न्याय प्रक्रिया।
→ केसों का तेजी से निपटान।

किए गए सुधार →

1) केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम'

2) राज्य सरकारों की विभिन्न पहलें।
→ बिहार राज्य की गाँव की भूमि संबंधी जानकारी पोर्टल पर डालना।
→ कर्नाटक सरकार का भूमि रिकार्ड डिजिटलीकरण कार्यक्रम

डिजिटल क्रांति का लाभ हम हर रूप में उठा सकें इसके लिए कृषि क्षेत्र में भी इसका पहुँचना आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन-मेरिट सब्सिडी के लिए निधि (फंड) उपलब्ध कराने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति, भारत में कुछ राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट के कगार पर धकेल रही है। इस संदर्भ में, भारत में सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies is pushing a few states in India to the brink of a deep fiscal crisis. In this context, discuss the need to rationalise the subsidy regime in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 'रेवड़ी संस्कृति' पर व्यंग्य किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर सुनवाई भी हो रही है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में चीजें बांटने के वादे पर रोक लगनी चाहिए।

नान मेरिट सब्सिडी से तात्पर्य ऐसी चीजों को मुफ्त या सस्ता देना है जो जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं करती बल्कि केवल अल्पकालिक होती है। जैसे - मुफ्त साइकल, पेट्रोल पर सब्सिडी आदि।

राजकोषीय संकट की ओर जाते राज्य -

↳ द० भारत के राज्यों में मुख्यतः मुफ्त चीजें बांटने की

संस्कृति रही है, जिसके कारण तमिलनाडु जैसे राज्य अपनी संपूर्ण क्षमता का दोहन आज तक नहीं कर पाए व आंध्रप्रदेश पीछे रह गया।

→ झारखंड जैसे राज्यों में पेट्रोल व डीजल पर सब्सिडी उनके पिछड़ेपन को और बढ़ाती है।

→ दिल्ली में चीजें अभी ठीक हैं, पर यह संस्कृति लगातार बढ़ना हानिकारक हो सकता है।

आगे की राह > 1) राजनीतिक दलों के मध्य एक स्वस्थ चर्चा के माध्यम से इन्हें रोकने पर सहमति बने।

2) मेरिट सब्सिडी को प्रोत्साहित किया जाए।

3) सब्सिडी व्यवस्था में व्याप्त प्रशासनिक छिद्र (लूपहोल) समाप्त किए जाएं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. सूक्ष्म-सिंचाई में कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में परिवर्तित करने की वृहद् क्षमता है। दिए गए कथन की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Micro-irrigation has tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss the given statement in the context of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सूक्ष्म सिंचाई, बाढ़ सिंचाई की विपरीत व्यवस्था है, सूक्ष्म सिंचाई में लक्षित रूप से पौधों तक जल को पहुँचाया जाता है जिससे केवल जरूरतयोग्य जल का ही उपयोग किया जाए। बूँद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई इसके उदाहरण हैं।

सूक्ष्म सिंचाई के लाभ →

1) भारत में 80% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है जिसके अप्रत्याशित रूप से कम होने की संभावना है।

2) मृदा की उर्वर क्षमता बाढ़ सिंचाई से घटती है, जो उत्पादन घटाती है, इससे उसे रोका जा सकेगा।

चुनौतियाँ —
- लागत अधिक
- रखरखाव कठिन
- पर्याप्त धन आवंटन नहीं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — इसके माध्यम से पुरानी कई योजनाओं का एकीकरण कर दिया गया। इसमें सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के अलावा सूक्ष्म सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया है, हर खेत को पानी तथा 'पर ड्राप मोर क्राप' (Per drop more crop) के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन भारतीय कृषि के सिंचाई अवसंरचना को बदलने का दम रखता है।

कृषि को विकसित किए बिना हम 2047 तक विकसित बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते तथा इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

5. भारत के विशाल संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपीय देशों (PSIDS) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Given its vast resources and technical expertise, India can play a key role in assisting the Pacific Small Island Developing States (PSIDS) in dealing with the impact of climate change. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपीय देशों (PSIDS) से तात्पर्य प्रशांत महासागर में स्थित उन द्वीपीय देशों से है जो अपेक्षाकृत कम विकसित हैं तथा जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व पर खतरे का सामना कर रहे हैं। जैसे - फिजी, सोलोमन द्वीप इत्यादि।

भारत की भूमिका →

1) भारत एक संसाधन संपन्न देश है, अतः अपने संसाधनों का उपयोग कर इनकी मदद कर सकता है। जैसे - मानव संसाधन की मदद से स्वास्थ्य अवसंरचना निर्माण में मदद।

2) तकनीकी विशेषज्ञता वाला देश भारत PSIDS देशों में तकनीकों के प्रयोग से खतरों को कम करने में मदद कर सकता है। जैसे- CDRI के माध्यम से प्रयास।

3) भारत इन छोटे देशों की आर्थिक सहायता भी कर सकता है।

4) भारत, UNEP, UNFCCC आदि संस्थाओं में इन देशों की सुभेद्यता का मुद्दा उठाकर विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन मानव द्वारा जनित सबसे बड़ी आपदा है जिसे कोई देश अकेले नहीं लड़ सकता, इसलिए भारत को भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्व की ही तरह आगे भी निभाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. हालिया "पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR)" का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा प्रत्यास्थता विकसित करना है। इस संदर्भ में, इस योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्क की विवेचना कीजिए और इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The recent "Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj (DMP–MoPR)" aims to develop disaster resilience at the grassroots level. In this context, discuss the rationale behind the formulation of the Plan and highlight its key components. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में आपदाओं के प्रति देश की लगातार बढ़ती सुभेद्यता को देखते हुए जमीनी स्तर पर उससे लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया है, जो पंचायतों के स्तर से यह प्रबंधन शुरू करेगी।

योजना निर्माण के कारक →

1) केंद्र व राज्य स्तर पर बनाई गई योजनाएँ उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप नहीं होतीं, जो प्रभावित है।

2) पंचायती कर्मचारी व स्थानीय लोगों की क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं किया जा सकता।

3) ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध पारंपरिक विशेषज्ञता को भी आपदा प्रबंधन ढांचे में लाने हेतु।

योजना के प्रमुख घटक -

- प्रत्येक पंचायत द्वारा उस क्षेत्र में आने वाली आपदाओं की पहचान करना।
- आपदा से निपटने की प्रक्रिया में पहले स्तर पर पंचायत का होना।
- राज्य के अन्य विभागों के साथ समन्वय।

आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना निर्माण तथा अन्य उपायों के साथ आपदा से निपटने में उस क्षेत्र विशेष के लोगों की भागीदारी बढ़ाना भी महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

7. राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) के उपयोग से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the internal security implications emanating from the use of Emerging And Disruptive Technologies (EDT) by state and non-state actors. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उभरती व विघटनकारी प्रौद्योगिकी (EDT) से तात्पर्य उन नए प्रकार के विध्वंशक उपकरणों व तकनीकों से है जो लगातार नयी आती प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं तथा किसी क्षेत्र/देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। जैसे- ड्रोन, साइबर हमले, रोबोट द्वारा हमले आदि।

आंतरिक सुरक्षा पर खतरा -

1) इन तकनीकी हथियारों की लगातार विकसित होती प्रकृति के कारण रोकने के उपाय विफल हो जाना।

2) भारतीय लोगों में इनके प्रति जागरूकता का अभाव।

3) सीमा पर लगातार खतरों में वृद्धि। जैसे - पठानकोट में ड्रोन हमला।

4) राज्य व गैर राज्य अभिकर्ताओं (जैसे - चीन, पाकिस्तान, ISI) की इन्हें उपयोग करने में भूमिका।

5) इनकी विध्वंसकारी प्रवृत्ति जो व्यापक पैमाने पर जन-धन हानि करते हैं।

6) इनके किसी संगठन से जानकारी के लिंक जोड़ना कठिन। जैसे - ड्रोन / रोबोट पकड़े जाने पर भी कोई जानकारी नहीं।

आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना देश आजादी का अमृत महोत्सव पूरी धूम-धाम से नहीं मना सकता, इसलिए हर प्रकार के खतरे से पूरी क्षमता के साथ निपटना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में भारत द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Identify the impediments faced by India in boosting its defence exports. Also, discuss the steps taken by the government in this regard. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत द्वारा वर्ष 2021 में केवल 13000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया जो चीन, रूस, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में नगण्य है।

रक्षा निर्यात में बाधाएँ -

1) 70% रक्षा निर्यात निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्र अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता।

2) निर्माण अवसंरचना का अभाव।

3) नए प्रकार के उपकरणों के निर्माण तथा अनुसंधान पर न खर्च किया जाना।

↳ भारत अपने कुल रक्षा बजट का केवल 1% अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका 6%।

4) विभिन्न विकासशील व गरीब देशों की पहचान कर उनकी जरूरत के अनुसार रक्षा उपकरण निर्माण नहीं किया जाता।

हाल में उठाए गए कदम –

1) सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन व निर्यात नीति 2020 बनाई गई।

2) लाइसेंस को आसान करने हेतु रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) को नोडल बनाया गया।

3) उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में रक्षा निर्माण गलियारे।

4) स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु idex

एक सुरक्षित देश के रूप में उभरने के लिए भारत को न सिर्फ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा, बल्कि रक्षा निर्यात भी बढ़ाना होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. अंतरिक्ष मलबे से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस खतरे से निपटने के लिए हाल के दिनों में कीं गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the multiple issues associated with space debris. Also, state the initiatives taken in recent times to tackle this menace. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अंतरिक्ष मलबे से तात्पर्य करमन रेखा (100 km.) से ऊपर के अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों, पिंडों के अवशेषों का होना है। जिनका लगातार बढ़ते जाना धरती पर नयी चुनौतियों को बढ़ाता है।

अंतरिक्ष मलबे से जुड़े मुद्दे -

- अन्य देशों के उपग्रहों को खतरा।
- संचार बाधित हो सकता है।
- धरती पर गिरने पर व्यापक नुकसान
- प्रदूषण को बढ़ाना।

अमेरिका की चीन व रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा फ्रांस की एस्टर-एक्स जैसी सैन्य अंतरिक्ष

गतिविधियों ने इसे हाल के वर्षों में और बढ़ाया है तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियम का न होना समस्या को और गंभीर कर रहा है।

किए गए प्रयास –

1) ब्रिटेन द्वारा सर्रे विश्वविद्यालय के साथ इसके अध्ययन व रोकने हेतु Techdemosat भेजा गया।

2) जापान द्वारा हाल ही में भेजा गया एक उपग्रह जो अपने आप को स्वतः ही नष्ट कर लेगा।

अंतरिक्ष, मानव की बढ़ती महात्वकांक्षाओं का शिकार होने वाला अगला तत्व बनेगा। पर इसे बचाए रखने के लिए अंतरिक्ष मलबे जैसी समस्याओं पर संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को अपनाने से उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के अधिक समावेशी और सुलभ बनने की संभावना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The adoption of Open Network for Digital Commerce (ONDC) in India is expected to make e-commerce more inclusive and accessible for consumers. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स एक प्रकार से भारतीय ई-कामर्स बाजार का लोकतांत्रीकरण करने का प्रयास है, जिसके द्वारा एक व्यापारी विभिन्न प्लेटफार्म पर अपने उत्पादों को अंकित कर आसानी से बेच सकेगा। भारत में इले० व सूचना प्रौद्यो० मंत्रालय के निर्देश पर यह बनाया जा रहा है।

संभावित लाभ -

1) इससे प्रमुख लाभ उपभोक्ताओं को होगा → केवल कुछ ही चीजों में से चुनने की बाध्यता समाप्त।
→ हर प्रकार के व्यापारी से क्रय संभव।

2) अभी के एकाधिकार आधारित ई-कामर्स को हटाकर एक समावेशी ई-कामर्स तंत्र बनाया जाएगा जिसमें एक पिछड़े क्षेत्र का व्यापारी भी महानगरों में अपनी वस्तुएं बेच सकेगा।

चुनौतियाँ –

1) व्यापक रूप से डिजिटल संसाधनों तक सभी की पँहुच नहीं।
2) डिजिटल जागरूकता का अभाव।
3) प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ।

UPI के द्वारा जिस प्रकार वित्तीय क्षेत्र को सर्वजनसुलभ बनाया गया, ई-कामर्स में वही भूमिका ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स से अपेक्षित है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. यद्यपि, हाल ही में "क्षतिकारक" सरकारी मत्स्यन सब्सिडी को रोकने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के मंच पर एक समझौते पर सहमति बनी है, तथापि, भारत द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं से पता चलता है कि इस मामले में और अधिक वार्ता किए जाने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
While an agreement was recently reached at the WTO on a deal to curb "harmful" government fisheries subsidies, certain concerns raised by India suggests that the matter will require further negotiations. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वाँ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों के साथ एक प्रमुख मुद्दा मत्स्यन पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी का है जो मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई देशों (चीन, जापान) में व्यापक रूप से दी जाती है।

WTO का फैसला ->

1) अविनियमित, अनियंत्रित तथा क्षतिकारक सब्सिडी को रोकने पर सहमति।

www.visionias.in

2) मछुआरों के समग्र विकास के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर व्यापक सहमति नहीं बन पाई। जैसे- नाव खरीदने, कोल्ड स्टोरेज आदि पर।

भारत की चिंताएँ >

1) अनियंत्रित, अविनयमित तथा क्षतिकारक सब्सिडी के संदर्भ में स्पष्ट परिभाषा का अभाव।

2) विकासशील व पिछड़े देशों के हितों को ध्यान में न रखा जाना।

3) चीन, जापान जैसे देशों द्वारा अत्यधिक दोहन किए जाने के बाद भी पर्याप्त कार्यवाही नहीं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4) व्यापक चर्चा तथा पूर्ण तटस्थ विश्लेषण का न होना।

WTO के भीतर विद्यमान संरचनात्मक कमियाँ अब उसके हर निर्णय पर विवाद खड़ा कर रही हैं। इसलिए उसमें व्यापक सुधार के साथ ही व्यापक चर्चा के बाद स्पष्ट निर्णय किए जाने चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. सड़क निर्माण क्षेत्रक में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) से जुड़े लाभों के बावजूद, विभिन्न कारणों से इसमें रुचि कम हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite the advantages that are associated with the hybrid annuity model (HAM) in the road construction sector, the interest in it has moderated due to various reasons. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाइब्रिड एन्युटि माडल (HAM)

सड़क निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक प्रकार है। इससे जुड़े कई प्रकार के लाभों के कारण यह सर्वाधिक उपयोग किया गया PPP माडल है, पर हाल के वर्षों में इसमें कमी आयी है।

HAM माडल → इसके तहत सड़क निर्माण हेतु आवश्यक खर्च केवल कुछ प्रतिशत सरकार प्रारंभ में निजी क्षेत्रक को देती है तथा शेष राशि की व्यवस्था करके सड़क निर्माण की पूरी जिम्मेदारी

निजी क्षेत्र पर होती है। सरकार बाद में, सड़क निर्माण के बाद मालिकाना हक अपने पास ले लेती है, तथा किश्तों में एन्युटी के रूप में निजी क्षेत्र को भुगतान किया जाता है।

इससे लाभ -

1) सरकार पर तत्काल रूप से आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है।
2) सड़क निर्माण संबंधी सभी दायित्व निजी क्षेत्र पर है।
3) मालिकाना हक सरकार के पास बना रहता है।
4) निजी क्षेत्र को भी निश्चित प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इन्हीं लाभों के कारण भारतमाला परियोजना में 50% से ज्यादा सड़कें इस मॉडल पर बनाई जा रही हैं।

अब कमी आने के कारण →

1) निजी क्षेत्र पर बोझ ज्यादा होने के कारण कम रुचि लेना।

2) सरकारी अधिकारियों व निजी लोगों के बीच शर्तों व नियमों का स्पष्ट रूप से तय न हो पाना।

आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण घटक के रूप में सड़क है, जिसका अकेले सरकार द्वारा निर्माण किया जाना वहनीय नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. मौजूदा एम. एस. पी. खरीद व्यवस्था न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही कृषि-पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही, मौजूदा एम. एस. पी. व्यवस्था में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The existing MSP procurement regime is neither economically nor agro-ecologically sustainable. Elaborate. Also, evaluate the alternative approaches that can be adopted to improve the existing MSP regime. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही मे समाप्त हुए कृषि आंदोलनों ने एम. एस. पी. (MSP) व्यवस्था के सुधार हेतु पुन: आंदोलन करने की बात कही है तथा समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा इस पर सवाल उठाया जाना इसमें निहित कमियों की ओर इशारा करते है।

एम. एस. पी. व्यवस्था के अंतर्गत फसल सीजन शुरू होने से पहले लगभग 18 फसलों पर आर्थिक मामलो की मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिससे कम पर किसानों की फसल नहीं बिकेगी।

आर्थिक दृष्टि से कमियाँ -

1) चुनावी प्रतिस्पर्धा में राजनीतिक दलों द्वारा लगातार इसमें वृद्धि की जा रही है।

2) इसकी कीमतें ज्यादा होने से निजी क्षेत्र ने इसमें रुचि लेना कम कर दिया है, जिसके कारण सारी खरीददारी भारतीय खाद्य निगम को ही करनी पड़ रही है।

संधारणीयता न होना -

→ इसके तहत केवल गेहूं, चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों पर जोर दिया जा रहा है, इससे

समस्याएं
- → ये ज्यादा जल दोहन वाली फसलें हैं।
- → मृदा की उर्वरता घटती जाना
- → दलहन, मोटे अनाज, सब्जियों पर ध्यान न देना, जिससे उनकी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कीमत हर साल बढ़ती है।

आवश्यक सुधार –

1) MSP- व्यापक विशेषज्ञ चर्चा तथा डेटा विश्लेषण के बाद तय हो।

2) विविधीकरण किया जाए तथा मोटे अनाज, सब्जियों पर भी ध्यान दिया जाए।

3) पिछड़े क्षेत्रों के किसानों से भी MSP पर खरीद सुनिश्चित की जाए।

MSP व्यवस्था किसानों के लिए एक वरदान की तरह है जो समय के साथ उनके लिए अभिशाप न बने इस संबंध में कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता से जूझ रहा है। भारत की मौजूदा बफर स्टॉक नीति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
It is being argued that India is struggling with overflowing foodgrains in warehouses. Discuss the statement in view of the existing buffer stock policy of India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत की MSP व्यवस्था की एक कमी यह भी है कि लगातार बढ़ते खरीद के बोझ के कारण भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर जहाँ एक ओर आर्थिक दबाव बढ़ा है वहीं इसके गोदामों में खाद्यान्न की अधिकता के कारण खाद्यान्न सड़ रहे हैं।

भारत में खाद्यान्न की अधिकता : विवेचन -

1) FCI के गोदामों में खाद्यान्न का भंडार जल्द ही 1000 मीट्रिक टन को छू लेगा जो यह दर्शाता है कि आवश्यकता से ज्यादा भंडारण किया गया है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2) हर वर्ष बारिश के मौसम में देश के विभिन्न भागों से खाद्यान्न सड़ने की खबरें आना भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

परंतु भारत की लगभग 20% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है जिसकी दोनों टाइम भोजन तक पहुंच नहीं है तथा वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। अर्थात् कमी खाद्यान्नों की अधिक खरीद से ज्यादा उसके वितरण की है जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की अदक्षता उजागर होती है।

भारत की मौजूदा बफर स्टाक नीति के हिसाब से FCI को 400MT खाद्यान्न बफर स्टाक के रूप में रखना है।

आवश्यक सुधार –

1) TPDS प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं तथा गोदामों में सड़ते खाद्यान्न को जरूरतमंद तक पँहुचाया जाए।

2) आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न के निर्यात पर भी ध्यान दिया जाए।

3) गेहूँ व चावल के अलावा फसलों की खरीदी को प्रोत्साहन।

भारत की कृषि व्यवस्था के उत्पादन को कृषि समाज के हित में प्रयोग करने के लिए FCI की भंडारण व वितरण नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. हाल ही में, सरकार ने सभी पत्तनों (पोर्ट्स) को वर्ष 2047 तक स्वयं को 'मेगा पोर्ट्स' के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में, पत्तनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और साथ ही, भारत की ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the government has asked all ports to prepare a master plan in order to become 'mega ports' by 2047. In light of this, discuss the challenges faced by ports and suggest remedial measures in order to propel India's blue economy. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पत्तन, किसी देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में ईंधन का काम करते हैं, जो व्यापार के आधारभूत तत्व होते हैं। भारत में पत्तन काफी समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनमें अवसंरचनात्मक, तकनीकी आदि सुविधाएँ देकर 'मेगा पोर्ट' में बदलना आवश्यक है।

भारतीय पत्तनों के साथ समस्याएँ-

1) भारत के बड़े पत्तन जैसे - मंगलौर, मुंबई भी बड़े व्यापारिक जहाजों के सामान उतारने की सुविधाएँ नहीं दे पाते जिसके कारण श्रीलंका का प्रयोग किया जाता है।

2) पत्तनों में अवसंरचनात्मक सुविधाएँ नहीं हैं; जैसे- भंडारण सुविधा, परिवहन सुविधा आदि।

3) प्रशासनिक कार्यवाही इन्हें और कमजोर बनाती हैं। जैसे- जल्दी क्लियरेंस न मिलना।

4) NITI आयोग के एक सर्वे के अनुसार भारत से एक सामान को अमेरिका भेजने में लगभग 60 दिन लगते हैं जिसमें ज्यादातर समय पत्तन पर लगता है।

~~ब्लू~~ इकोनामी से तात्पर्य सागरों व जलीय संसाधनों का प्रयोग कर आर्थिक विकास करने से है। जैसे- मत्स्यन, पाली ~~[illegible]~~ मेटलिक नाड्यूल्स आदि।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उपाय → (ब्लू इकोनामी हेतु)

1) पत्तनों को सुधारने के लिए वृहद् पत्तन, जल्दी अनुमति, अवसंरचना निर्माण पर ध्यान जो ब्लू इकोनामी को प्रोत्साहन देंगें।

2) सागरीय संसाधनों के संधारणीय दोहन पर जोर
- → पर्यटन
- मत्स्यन
- खनिज अन्वेषण

3) समुद्र से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग व निर्यात को प्रोत्साहन।

आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापना के लिए ब्लू इकोनमी के रूप में भी भारत को स्थापित होना होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. आय और संपदा में असमानता कार्बन असमानता में परिवर्तित हो जाती है। इस संदर्भ में, भारत के लिए कार्बन असमानता को दूर करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसे प्राप्त करने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Inequality in income and wealth translates into carbon inequality. In this context, discuss the significance of addressing carbon inequality for India and suggest ways to achieve it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कार्बन असमानता से तात्पर्य विभिन्न देशों तथा वर्गों के बीच अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्बन स्रोतों तक पंहुच की असमानता से है। यह असमानता एक प्रकार से आय की असमानता का परिणाम मानी जा सकती है।

आय की असमानता से कार्बन असमानता -

- भारत के ऊपरी 10% अमीर लोगों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 9 टन है जबकि निचले 10% का 1 टन/व्यक्ति है।
- आय की असमानता के कारण उत्पादन के स्रोतों तक पंहुच

सीमित हो जाती है जो कार्बन असमानता को जन्म देता है।

↳ इसी प्रकार यदि देशों के मध्य देखें तो अधिक आय वाले देश अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन ~~16 टन/व्यक्ति~~ 16 टन/व्यक्ति है जबकि भारत का 1.8 टन/व्यक्ति है।

कार्बन असमानता दूर करने का महत्व -

1) कार्बन के स्रोतों तक समाज के व्यापक वर्ग की पँहुच उनके सभी प्रकार से विकास के मार्ग खोलेगी।
2) इससे आय की असमानता दूर करी जा सकेगी।
3) भारत की कार्बन उत्सर्जन संबंधी नीति ज्यादा समावेशी बनेगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्राप्त करने के उपाय -

1) कार्बन समानता प्राप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग के नागरिकों की क्षमता निर्माण किए जाने की जरूरत है। जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास।

2) तकनीकों के प्रयोग से उत्सर्जन कम करने संबंधी उपाय में हर वर्ग की प्राथमिकता का ध्यान रखा जाए।

3) देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त नीतियाँ बनाई जाएँ।

देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करना हर प्रकार की असमानता को समाप्त करने का परिणाम होगा जिसमें कार्बन असमानता भी एक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. भारत में पिछले एक दशक के दौरान भूस्खलन की बढ़ती और नियमित घटनाओं के बावजूद, विकास के प्रमुख प्रतिमानों (पैरडाइम) में कोई मुख्य संशोधन नहीं किया गया है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite increased and regular occurrences of landslides over the past decade in India, the dominant development paradigm has largely not been modified. Examine. (Answer in 250 words)15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भूस्खलन एक आपदा है जिसमें बड़ी मात्रा में अवसाद, पत्थरों का प्रायः ऊँचे क्षेत्रों से निचले क्षेत्रों की ओर अचानक विस्थापन होता है जो व्यापक रूप से जनधन की हानि करते हैं।

भारत में प्रभाव क्षेत्र ⇒

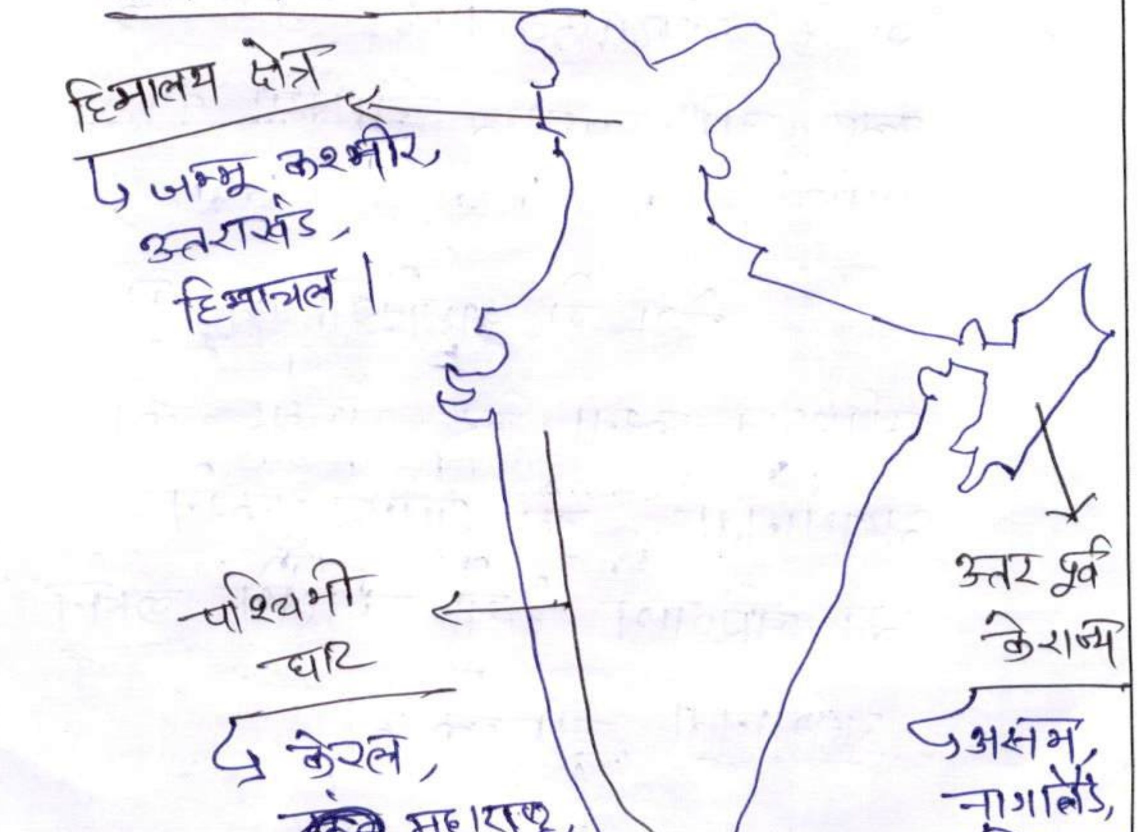

भारत में पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलन की बड़े पैमाने पर घटनाएँ देखने को मिली हैं खासकर हिमालयी क्षेत्रों में जो बाढ़, बादल फटना जैसी घटनाओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तबाही मचाती हैं। जैसे - 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2022 में अमरनाथ गुफा हादसा आदि।

कारण —
- अनियंत्रित विकास
  - पर्यावरण का ध्यान न रखना
  - संवेदनशील क्षेत्रों में भी बांध पावर प्लांट आदि निर्माण।
- जलवायु परिवर्तन।
  - अप्रत्याशित मौसम दशाएँ
- पर्यटन आदि का असंधारणीय रूप में बढ़ना।
- सरकारों द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिया जाना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इन सबमें प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों की भंगुरता को ध्यान में रखे बिना विकास किए जाना है, जिसमें अभी भी परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी लगातार नए पावर प्लांट बन रहे हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है तथा प्रशासन लगातार उदासीन बना हुआ है जो घटनाओं की भयावहता को और बढ़ाएगा।

आगे की राह →

1) हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रतिमानों को और कठोर किया जाए।

2) व्यापक सर्वेक्षण के बाद ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य हों।

3) सरकार व नागरिक सहयोग।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

18. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ वैध सीमा-पार प्रवाह को संतुलित करने के लिए भारत को एक स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India needs a smart border management system to balance legitimate cross border flows with national security interests. Discuss. Also, highlight the initiatives taken by the government in this regard. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्मार्ट सीमा प्रबंधन से तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा तथा अन्य विकास हेतु नयी तकनीकों का प्रयोग करना। जैसे - निगरानी हेतु ड्रोन, स्मार्ट बाड़ाबंदी, रोबोट का प्रयोग आदि।

सीमा प्रबंधन में चुनौतियाँ -

- अवैध घुसपैठ तथा आतंकी प्रवेश (जैसे- पाकिस्तान सीमा पर।
- संगठित अपराध का बढ़ना (पंजाब में ड्रग तस्करी।
- पर्याप्त अवसंरचना का अभाव (सड़क, हथियार आदि।
- सीमा से लगे क्षेत्रों का विकास न होना।

स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता -

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

1) सीमाओं पर सैनिकों की सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु। जैसे - आटोमैटिक हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट।

2) सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकना। जैसे - ड्रोन से निगरानी, बाड़बंदी।

3) संगठित अपराध खत्म करना।
   ↳ हथियार तस्करी, मानव दुर्व्यापार, ड्रग तस्करी रोकने हेतु स्मार्ट निगरानी।

4) सीमा से लगे क्षेत्रों में विकास के पर्याप्त अवसर पैदा करना भी सीमा प्रबंधन का एक हिस्सा है।

5) साइबर हमले, ड्रोन से हथियार गिराना जैसे नए प्रकारों के अपराधों से निपटने हेतु।

उठाए गए कदम –

1) सुरक्षा हेतु →
- वायु चेतावनी तथा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम (AWADS) अपनाना।
- हैदराबाद स्थित एक संस्था द्वारा तैयार एंटी ड्रोन तकनीक।
- बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बाड़ाबंदी।
- चीन सीमा पर इजराइल के ड्रोन की तैनाती।

2) अवसंरचना हेतु →
- चीनी सीमा पर दौलतबेग ओल्डी सड़क।
- 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' (चीनी सीमा के गाँव)
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

सीमा सुरक्षा ही देश के अंदर अन्य प्रकार की सुरक्षाओं का आधार है, जिसका स्मार्ट प्रबंधन समय की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. वैश्वीकरण और धन शोधन के बीच संबंध स्थापित करते हुए, इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Establishing linkages between globalisation and money laundering, discuss the initiatives taken at the national and international levels to combat it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

धन शोधन से तात्पर्य

कर चोरी, भ्रष्टाचार, अपराध या अन्य किसी गैर कानूनी स्रोत से अर्जित धन को पुन: कानूनी धन बनाने की प्रक्रिया से है।

धनशोधन से उत्पन्न खतरे

- सरकार को आर्थिक नुकसान
  - कर चोरी
- अपराध को बढ़ावा
- आतंकी फंडिंग जैसे कृत्यों में प्रयोग
- समाज में गलत प्रभाव पैदा करना
  - भ्रष्टाचार की भावना

वैश्वीकरण व धन शोधन में संबंध →

वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया के बाजारों, वित्तीय तंत्रों यहां तक कि नागरिकों के आपस में

जुड़ने से है, जो धनशोधन को कई प्रकार से आसान बना रहा है -

1) वित्तीय तंत्र जुड़े, तो विभिन्न देशों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर उसका परतीकरण (layering) कर लेना।

2) बाजार जुड़े, तो कम विनियमन वाले देश में फर्जी कंपनी बनाकर उनके माध्यम से धन की राउंड ट्रिपिंग (Round Tripping)

3) हवाला जैसी घटनाएं भी इसी का नतीजा।

हालांकि वैश्वीकरण ने कुछ हद तक इससे लड़ना आसान भी किया है → विभिन्न देशों की एजेंसियों में समन्वय।
→ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पहले →

1) राष्ट्रीय स्तर पर → धनशोधन निवारण अधि० 2002।

→ प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक आधिकार, जिसमें जाँच, जब्ती व गिरफ्तारी शामिल है।

→ Natgrid जो व्यापक डेटाबेस का कार्य करता है।

2) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर –

→ FATF (वित्तीय कार्यवाही कार्यबल) का मुख्य कार्य धनशोधन व आतंकी फंडिंग से लड़ना है।

→ राउंड ट्रिपिंग को खत्म करने हेतु वैश्विक न्यूनतम कर पर सहमति।

धनशोधन, वर्तमान समय की एक मुख्य चुनौती है जिससे निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत को बाह्य अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में अपनी कुछ पुरानी धारणाओं की समीक्षा करने और नए वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
There have been arguments that India needs to review some of its past assumptions about the nature of outer space and contribute to the development of new global norms. In this context, analyse India's stand in relation to the Artemis Accords. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बाह्य अंतरिक्ष से तात्पर्य करमन रेखा (100km.) से ऊपर के भाग से है, जो वर्तमान में अनुसंधान, संसाधन, सुरक्षा आदि कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है।

भारत की भूमिका →

1) पुरानी धारणा – भारत में हमेशा से अंतरिक्ष की तुलना में धरती पर जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करना चाहिए (डा. विक्रम साराभाई), ऐसी मान्यता रही है, पर हाल के वर्षों में भारत इससे बाहर निकला है तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों

में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया है।
जैसे - मंगलयान, IRNSS आदि।

↳ इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि भारत का वैश्विक शांति का दृष्टिकोण बाह्य अंतरिक्ष का दोहन करने से उसे रोकेगा।

↳ साथ ही भारत का बाह्य अंतरिक्ष के मामले में दूसरे देशों से ज्यादा सहयोग, डेटा ट्रांसफर, जैसे मुद्दों पर दृष्टिकोण भी प्राचीन माना जा रहा है।

2) आवश्यकता -

↳ बाह्य अंतरिक्ष के संपूर्ण व संधारणीय दोहन हेतु क्षमता निर्माण। जैसे - गगनयान।

↳ आर्टेमिस समझौता - जो NASA

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

के नेतृत्व में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, उपग्रह को चिन्हित करने, सहयोग, डेटा हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर किया गया है - पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तथा भारत को इसके समस्त गुण - दोषों के अध्ययन के बाद ही इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

बाह्य अंतरिक्ष वर्तमान समय के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है तथा भारत को इस संदर्भ में अपनी नीति में पूर्ण रूप से बदलाव करने की भी आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती हालांकि उसमें सुधार आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK